किए गए हैं। जहां भी संभव हो वहां अपशिष्ट का संसाधन के रूप में उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

एशियाई देशों के वनस्पति शास्त्रियों की बैठक

3610. **श्री अर्जुन जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एशिया जैविक सम्पदा को दोहन से बचाने के लिए एशियाई देशों के प्रमुख वनस्पतिशास्त्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या भारत के वनस्पतिशास्तियों ने भी इस बैठक में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या निष्कर्ष रहे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 26-28 अक्तूबर, 1992 को चियांग माइ (थाईलैंड) में वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइट्स) की पादप समिति की एक बैठक हुई जिसका उद्देश्य जैविक संपदा के व्यापार का जायजा लेना और साइट्स विनियमों के अन्तर्गत निवारक उपायों पर विचार-विमर्श करना था।

(ख) और (ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक ने इस बैठक में भाग लिया।

(घ) बैठक में साइट्स के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई और यह सिफारिश की गई कि कन्वेंशन के सभी सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइट्स को प्रजातियों और उनके व्युत्पन्नों का निर्यात और आयात मापदण्डों के अनुसार हो हो। यह भी सिफारिश की गई कि साइट्स विनियमों के कार्यान्वयन गैर-सदस्य देशों का भी निकट सहयोग प्राप्त किया जाए, इसके अलावा साइट्स प्रजातियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए सभी उचित उपाय किए जाएं।

Export of Marble from Aravalis

3611. SHRI RAM NARAYAN GOSWAMI :

SHRI SUNIL BASU RAY :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have permitted export of marble mainly from Aravalis at the cost of environment of the area; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) Export of Marble is not covered under Export Trade Control Order and is therefore, freely allowed. However, prior approval of Central Government is essential before a mining lease is granted in respect of any forest area and the approval, when accorded, is subject to effective implementation of environmental safeguards. In the case of Aravalis, the provisions of the Notification under Environment (Protection) Act, 1986 dated 7th May, 1992 are applicable.

Representation from Lok-Raj Suraksha Samiti regarding Pollution by M/s. Associated Distillery Limited

3612. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have received representation from Lok-Raj Suraksha